cess. The full positive impact of these measures on the economy may be vislble by the end of the 8th Plan period. Some initjal results have become noticeable in these months. They have been comprehensively documented in the Economy Survey presented to the Parliament on the 23rd. These results include: building up of foreign exchange reserves; pick up in rate of growth of exports to general currency area; revival of industrial growth and lowering of rate of inflation from 16 to less than 7 per cent. Moreover, the macro-economic stabilisation of the economy which is essential condition for the success of the measures for liberalisation and structural reforms has also been achieved. This has resulted in sharp lowering of fiscal deficit of the Government; reduction in government borrowing from the RBI and consequent lowering of the Inflation rate.

(b) As the Economy Survey 1992-93 points out the economic situation has substantially improved in the year 1992-93. There has been progress in overcoming the inflation improvlng the balance of payment situation and some recovery in industrial growth. Despite the irregularities In securities trading and the disturbed condition, in December 1992 and January 1993, the rate of growth of exports and industry have picked up. A rate of growth of 4 per cent for the economy may be achieved in 1992-93 which is significantly better than the growth of 1.2 per cent achieved during 1991-92.

(c) It is difficult to make any assessment of the achievements in employment and poverty eradication at this stage because the data for the period since July 1991 for these variables is not yet available.

ग्रामीण बैंक के निदेशक पद पर नियुक्ति के मामले में अनियमितताएं

920. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दबाव के कारण ग्रामीण बैंक के निदेशक पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त था, जैसा कि 5 जनवरी, 1993 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकशित हुआ है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है और उपरोक्त बैंकों में कितने निर्देशक नियुक्त किये गये हैं तथा निदेशकों के कितने पद भरे जाने शेष हैं ;

(ग) क्या निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई मापदंड/प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) मध्य प्रदेश के महाकौशल एवं झाबुआधार ग्रामीण बैंकों के निदेशक पद पर एक ऐसे व्यक्ति, जिस पर दस से भी अधिक आपराधिक मामले प्रमाणित हो चुके हैं, की नियुक्ति किस आधार पर की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ङ) सरकार ने दिनांक 5-1-93 के राष्ट्रीय सहारा में छपे समाचार को देखा है। झाबुआधार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित व्यक्तियों के पुलिस रिकार्ड प्रतिकूल नहीं है जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट

ने सूचित किया है । महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर के निदेशक मण्डल में नामांकन, पुलिस रिकार्ड और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई वर्तमान सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया गया है ।

(ख) से (घ) 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में इस समय 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है (नीचे देखिए) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1988 के अधिनियम 66 तक यथा संशोधित) के तहत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित अन्य सदस्य होते हैं :—

(i) केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य, जो न तो केन्द्र सरकार के अधिकारी हों और न ही राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक प्रयोजक बैंक या किसी अन्य बैंक के अधिकारी हों;

(ii) एक निदेशक जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी हो उसे बैंक द्वारा नामित किया जाना है;

(iii) एक निदेशक, जो राष्ट्रीय बैंक का अधिकारी हो, उस बैंक द्वारा नामित किया जाना है ;

(iv) दो निदेशक, प्रायोजक बैंक के दो अधिकारी हों, जिनका नामांकन उक्त बैंक द्वारा किया जाना है ; और

(v) संबंधित राज्य सरकार के दो अधिकारी जिनका नामांकन दो निदेशकों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है ।

इस प्रकार केन्द्र सरकार दो वर्षों के लिए या नए नामांकन किए जाने तक, प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल में 2 गर-सरकारी निदेशकों का नामांकन करती है । इस समय, देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बक हैं और इस प्रकार किसी एक निश्चित समय पर, 392 गैर सरकारी निदेशक होने चाहिए। इस समय गैर-सरकारी निदेशकों की 170 रिक्तियां हैं जिनमें से 48 स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन पर कोई पदाधिकारी नहीं हैं तथा शेष 122 रिक्तियां उन गैर-सरकारी निदेशकों की हैं जो अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पदों पर आसीन हैं क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्तियां अभी नहीं हुई हैं । भारत सरकार गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में ऐसे व्यक्तियों का नामांकन करती है जिन्हें कृषि लघु उद्योग या सम्बद्ध कार्यों का ज्ञान है और जो उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रचालन क्षेत्र के रहने वाले हों ।

विवरण

31-12-1992 के अनुसार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू व कश्मीर	3
पंजाब	5
राजस्थान	14
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	5
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
त्रिपुरा	1
बिहार	22
उड़ीसा	9
पश्चिम बंगाल	9
मध्य प्रदेश	24
उत्तर प्रदेश	40
गुजरात	9
महाराष्ट्र	10
आंन्ध्र प्रदेश	16
कर्नाटक	13
तमिलनाडु	3
केरल	2
योग	196